

रत्न सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

3 अक्टूबर, 1979

[वी.आर. कृष्णा अय्यर और पी.एन. शिन्धल, जे.जे.]

भारतीय दंड संहिता- धारा 304 ए - जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना - दो वर्ष की कठोर कारावास की सजा - यदि अत्यधिक हो।

सजा - गाड़ी चलाने के अपराधों के लिए सजा - सुधार की नीति - बेहतर ड्राइविंग के लिए पाठ्यक्रम - कभी-कभी पैरोल - विधायी कार्रवाई - आवश्यकता।

याचिकाकर्ता, एक भारी ऑटोमोबाइल के चालक को लापरवाही से वाहन चलाने के कारण एक स्कूटर चालक की मौत के लिए आई पी सी की धारा 304 ए के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि दुर्घटना के लिए कोई और जिम्मेदार है, विचारण और अपीलिय न्यायालयों द्वारा खारिज कर दी गई थी।

इस सवाल पर कि क्या सजा अत्यधिक थी-

**अभिनिर्धारित किया:** जल्दबाजी और लापरवाही सापेक्ष अवधारणाएँ हैं, पूर्ण अमूर्तताएँ नहीं। आईपीसी की धारा 304 ए और लापरवाही के तहत कानून में भारी वाहनों की लापरवाही से गाड़ी चलाने और तेज गति से चलने वाले खतरों की घातक आवृत्ति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए, रेज़ इप्सा लॉक्विटुर की भूमिका को सावधानी से लागू करना उचित है। जब किसी की जान चली जाती है और गाड़ी चलाने की परिस्थितियाँ कठोर होती हैं, तो कोई करुणा दिखाई जा सकती है। [848 ए-बी, डी]

याचिकाकर्ता दोषसिद्धि और सजा के प्रश्न पर कोई विचार का पात्र नहीं है। [848 सी]

[(क) सजा देने में सुधार की नीति होनी चाहिए। जब सजा ड्राइविंग अपराधों के लिए होती है, तो राज्य को जिम्मेदारी की जीवंत भावना के साथ बेहतर ड्राइविंग के लिए एक पाठ्यक्रम जोड़ना चाहिए और गरीब परिवारों वाले पुरुषों के मामलों में, राज्य कभी-कभार पैरोल और सुधारात्मक पाठ्यक्रम पर विचार कर सकता है। [ 848 ई-एफ]

(ख) पीड़ित को मुआवजा अभी भी आपराधिक कानून का लुप्त होने वाला बिंदु है। अपराध के पीड़ित, और कैदी के आश्रितों की पीड़ा, कानून

का ध्यान आकर्षित नहीं करती है। व्यवस्था की इस कमी को विधानमंडल द्वारा दूर किया जाना चाहिए। [848-जी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: विशेष अवकाश याचिका (आपराधिक)  
संख्या 953/1979

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1021/1978 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 13-10-1978 से उत्पन्न।

ए. एस. सोहल और आर. सी. कोहली, याचिकाकर्ता की ओर से।

न्यायालय का आदेश दिया गया -

कृष्ण अय्यर, न्यायाधिपति.- अनुच्छेद 136 के तहत विशेष छुट्टी के लिए यह याचिका एक ट्रक चालक द्वारा है जिसके घातक हाथों ने एक भारी वाहन चलाते हुए एक स्कूटर चालक की जान ले ली है - एक घातक दृश्य इन दिनों हमारे कस्बों और शहरों में बहुत आम हो गया है। यह एक ऐसा मामला है जो एक घटना से अधिक एक बानगी है और हमारे राजमार्गों के भयावह पाप के रूप में क्रूर लेकिन दुखद यातायात अराजकता और सार्वजनिक परिवहन की विश्वासघाती असुरक्षितता का प्रतीक है, जो गतिशीलता के साधनों की तुलना में घातक सुविधाओं की तरह अधिक हैं। अधिकांश बीमारियों की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में अधिक लोग मरते हैं,

इतना ही नहीं भारतीय राजमार्ग देश के शीर्ष हत्यारों में से एक हैं। सड़कों के अच्छे रखरखाव में राज्य की गड़बड़ी की लगातार शिकायतों के साथ क्या, राज्य परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए जनहित याचिका की अनुपस्थिति, और नागरिकों की अत्याचार चेतना की कमी, और कानून में कानून बनाने में उपेक्षा के साथ क्या- दोष दायित्व और राजमार्ग प्रणाली की क्षमताओं से परे भारी शुल्क वाले वाहनों को सड़कों पर शामिल करने से, भारतीय परिवहन एक खतरनाक प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है जो यात्रा को मौत के समान बना देता है। ऐसा लगता है जैसे यातायात नियम लगभग खत्म हो गए हैं और पुलिस चेकिंग ज्यादातर नदारद है। अराजकता की इन प्रक्रियाओं के कारण, सार्वजनिक सड़कें अब मौत के जाल में छिपी हुई हैं। राज्य को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में लोकप्रिय संगठनों की सक्रियता, भीषण दुर्घटनाओं के लिए भयावह प्रचार और सख्त ड्राइविंग लाइसेंसिंग और सख्त वाहन को बढ़ावा देने के माध्यम से जमे हुए उदासीनता से परे सक्रिय पुलिस उपस्थिति के माध्यम से सड़क सुरक्षा उपाय प्रदान करना चाहिए। निरीक्षण, ऐसा न हो कि मानव जीवन को राजमार्ग के उपयोग का मौका ही न मिले।

सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आँकड़ों के कारण ये कड़ी टिप्पणियाँ आवश्यक हो गई हैं। कई खतरनाक ड्राइवर सफलतापूर्वक न्यायालय में तर्क देते हैं कि गलती किसी और की है। वर्तमान मामले में, इस तरह की

याचिका को यथार्थवादी स्पर्श के साथ आगे रखा गया था लेकिन नीचे की न्यायालयों ने इसे सही ढंग से खारिज कर दिया। भारी वाहनों को गलत दिशा में पार्क करना, ट्रैफिक सिग्नल को चुपचाप पार करना, सड़क के बाईं ओर चलने की उपेक्षा करना, नशे की हालत में वाहनों को आड़े-तिरछे चलाना, बिना हेलमेट के स्कूटर चलाना और पूरे परिवार को पीछे बैठाकर बिना सोचे-समझे चलना। साइकिल चलाना और पैदल चलना, स्टेज कैरिज की दमघोंटू जाम-पैकिंग और मिनी-बसों की नरक-ड्राइविंग, खतरनाक अनुमानों के साथ ट्रकों की ओवरलोडिंग और सबसे ऊपर, पुलिस आदमी, यदि कोई हो, असहाय उपस्थिति से साबित करना कि कानून मर चुका है इस माहौल में हाथापाई का आरोप है - ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को मौत द्वारा सम्मन का दैनिक, प्रति घंटा दृश्य है जो यातायात कानूनों की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हुए सड़कों पर निकलते हैं। हमें उम्मीद है कि भारत का प्रत्येक राज्य जीवन के प्रति गंभीर संवेदनशीलता और श्रद्धा के साथ राजमार्ग की उपेक्षा, राज्य परिवहन उल्लंघनों और इसी तरह की मानवीय कीमत पर ध्यान देगा।

हालाँकि, यह आरोपी को 'अंधा लेविथान को पागलपन में' लापरवाही से चलाने से छूट नहीं देता है। यदि हम प्रभु के शब्दों को अपना सकें, तो ग्रीन एम.आर.: 'यह मुश्किल से उस ट्रक ड्राइवर के मुंह में रहता है जो आग से खेलता है और जली हुई उंगलियों की शिकायत करता है।'

उत्तावलापन और लापरवाही सापेक्ष अवधारणाएँ हैं, पूर्ण अमूर्तताएँ नहीं। हमारी वर्तमान परिस्थितियों में, आईपीसी की धारा 304-ए और लापरवाही के नियम के तहत कानून को भारी वाहनों की लापरवाही से गाड़ी चलाने और तेज गति से चलने वाले खतरों की घातक आवृत्ति पर उचित ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार देखा जाए तो, निस्संदेह, रेस इप्सा लोकिटूर के नियम को सावधानी से लागू करना उचित है। सम्मोहक साक्ष्यों को छोड़कर, पारंपरिक बचाव व्यावहारिक न्यायालय के समक्ष विफल हो जाने चाहिए और उन्हें संक्षिप्त कर दिया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखने पर, हम आश्चर्य हैं कि वर्तमान मामला दोषसिद्धि के प्रश्न पर विचार करने योग्य नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि 2 साल के कठोर कारावास की सजा अत्यधिक है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के पास पालन-पोषण करने के लिए एक बड़ा परिवार है और ट्रक के मालिक ने उसके परिवार को ठंड में छोड़ दिया है। जब किसी की जान चली गई हो और ड्राइविंग की परिस्थितियाँ कठिन हों, तो कोई दया नहीं दिखाई जा सकती। हम सजा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हालांकि मालिक अक्सर नैतिक रूप से निर्दोष नहीं होता है।

फिर भी, सजा देने में सुधार की नीति होनी चाहिए। इस ड्राइवर को, यदि उसे एक अच्छा ड्राइवर बनना है, तो उसे मानव जीवन और अंग को

संभावित चोट के विशेष संदर्भ में, यातायात कानूनों और नैतिक जिम्मेदारी में बेहतर प्रशिक्षण देना होगा। इसलिए, इस क्षेत्र में सजा के साथ ये घटक भी होने चाहिए। हम आशा करते हैं कि जब ड्राइविंग अपराधों के लिए सजा दी जाएगी तो राज्य बेहतर ड्राइविंग के साथ-साथ जिम्मेदारी की जीवंत भावना भी जोड़ देगा। हो सकता है, राज्य गरीब परिवारों वाले पुरुषों के मामलों में, पुराने नियमों की कठोरता के बिना, जो सरकारी विवेक के अधीन हैं, उचित आवेदन पर कभी-कभी पैरोल और सुधारात्मक पाठ्यक्रमों पर विचार कर सकता है।

दोषी के परिवार का उत्पीड़न एक वास्तविकता हो सकती है और अफसोसजनक है। यह हमारे न्यायशास्त्र की कमजोरी है कि अपराध के पीड़ित और कैदी के आश्रितों की परेशानी कानून का ध्यान आकर्षित नहीं करती है। दरअसल, पीड़ित को मुआवजा अभी भी हमारे आपराधिक कानून का लुप्त बिंदु है। यह व्यवस्था की कमी है जिसे विधायिका द्वारा सुधारा जाना चाहिए। हम सिर्फ इस मामले पर ध्यान दिला सकते हैं। उम्मीद है कि कल्याणकारी राज्य हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में यातायात न्याय के लिए बेहतर विचार और कार्रवाई प्रदान करेगा। हम विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हैं।

एन.वी.के.

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

**अस्वीकरण-** इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

\*\*\*\*\*